दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार 17 जुलाई 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 289

महत्वपूर्ण एवं खास

मंत्री टीएस सिंहदेव ने छोड़ा पंचायत विभाग

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत स्वास्थ्य व जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज पंचायत विभाग की जिम्मेदारी छोड़ दी है। वे स्वास्थ्य एवं जीएसटी मंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। मंत्री सिंहदेव के इस्तीफे की खबर से हडक़ंप मच गया लेकिन वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई है कि सिंहदेव ने सिर्फ पंचायत विभाग का त्याग किया है। मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अभी शासन स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

सिर दर्द ने बिगाड़ दी मासूम बच्ची की सूरत, अब चेहरा देखकर डर जाएंगे आप

रांची (आरएनएस)। झारखण्ड के गिरिडीह जिला से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां, एक 11 साल की लडक़ी का सिर दर्द के बाद जो हाल हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह जायेगा। बताया जा रहा है कि खुशबू कुमारी नाम की लडक़ी 6 महीने पहले बिलकुल ठीक थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे सिर दर्द हुआ जिसके बाद धीर- धीरे उसकी सूरत बिगाड़ गई। बच्ची के माता-पिता भी गरीब हैं। बच्ची ऐसे कठिन हालातों से गुजर रही है कि उसके इलाज के लिए घर वाले भी पैसा नहीं लगा सकते। ये पूरा मामला गिरिडीह जिला के गिरिडीह प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत का कल्हामांझो है। हालाँकि, बच्ची किस बीमारी से पीड़ित है उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो डालकर सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई जा रहे है।

कर्नाटक में सरकारी कार्यालयों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से प्रतिबंध हटा

बेंगलुरू (आरएनएस)। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने शनिवार को सरकारी कार्यालयों के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया है। कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग (डीपीएआर) के उप सचिव ने आदेश वापस ले लिया। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ द्वारा एक सबमिशन के बाद सरकार ने सरकारी कार्यालयों में फोटो, वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। आदेश में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोग काम के घंटों के दौरान सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियो लेने आए और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की बदनामी हो रही है। वीडियो और फोटो बनाने से महिला कर्मचारियों को परेशानी होती है। राज्य सरकार ने दावा किया कि उसने इस सबमिशन के बारे में तथ्यों को पूरी तरह से सत्यापित कर लिया है और पाया कि सरकारी कार्यालयों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है और इस संबंध में निषेध आदेश जारी किए हैं।

बिहार : राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस, राजद में मिटीं दूरियां, विपक्षी दल एकजुट

पटना (आरएनएस)। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस में बढ़ी दूरियां घटती नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार का विपक्ष साथ नजर आ रहा है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन भी एकजुट है। भले ही सत्ताधारी गठबंधन को अभी भी विपक्ष का मत मिलने की आस है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा शुक्रवार को पटना पहुंचे और विपक्षी दलों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यशवंत सिन्हा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार योग्य और अनुभवी हैं। ये राष्ट्रपति बनेंगे तो महज रबर स्टांप नहीं रहेंगे, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बैठक में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा, सीपीआई के रामबाबू कुमार, सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी, भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम सहित विपक्षी दलों के सभी विधायक और सांसद मौजूद थे। विपक्षी दलों के विधायक और सांसदों ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देकर जिताने का संकल्प लिया। उल्लेखनीय है कि राजद और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ महीने से दूरियां बढ़ी दिखती रही थीं। बिहार विधानसभा उपचुनाव हो या विधान परिषद चुनाव दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। लेकिन, राष्ट्रपति चुनाव में एक साथ नजर आए।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, 6 घंटे में पूरा होगा चित्रकूट से दिल्ली का सफर

उरई (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस तरह चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर छह घंटे में पूरा हो सकेगा। दिलचस्प यह कि यूपीडा ने यह एक्सप्रेसवे 36 महीने के बजाए 24 महीने में बनाकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। मोदी ने कहा कि यह एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड को विकास और स्वरोजगार से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले यह माना जाता था कि बेहतर सडक़ों का लाभ सिर्फ बड़े शहरों को ही मिलता है, लेकिन अब सरकार बदली है तो मिजाज भी बदला है। अब छोटे शहरों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है और सही मायने में यही सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है।

इस अवसर पर योगी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास का जीवंत प्रमाण है। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र को नई पहचान दिलाकर यहां औद्योगिक निवेश को आमंत्रित करने का नया माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि 'बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे' एवं 'इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' के निर्माण से प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह एक्सप्रेस-वे उ.प्र. के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक और केन्द्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मतदाताओं को लुभाने के लिये जनता में मुफ्त की सौगात बांटने को देश के लिये घातक बताते हुए कहा है कि देश में मुफ्त की रेवड़ी बांट कर वोट बटोरने की परिपाटी पनप रही है, ये 'रेवड़ी कल्चर' देश के लिये घातक है और सभी को मिलकर इस 'रेवड़ी कल्चर' को राजनीति से हटाना है।

मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का यहां कैथेरी गांव में लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को आगाह किया कि मुफ्त की वस्तुयें बांटकर वोट बटोरने वाली राजनीति से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यहां विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना है।

मोदी ने लोगों से इस परिपाटी को मिटाने का आह्वान करते हुए कहा, रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर, उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही, बल्कि मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है।

गौरतलब है कि मोदी ने फरवरी 2020 में 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने चार लेन वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का चित्रकूट में शिलान्यास किया था। इसका आज उद्घाटन होने से बुंदेलखंड के सात जिले चित्रकूट से इटावा तक, एक्सप्रेस वे के माध्यम से दिल्ली और लखनऊ से सीधे जुड़ गये हैं।

दिल्ली और लखनऊ से सीधे जोडऩे वाले 296 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के जरिये दिल्ली से चित्रकूट तक की 630 किमी की दूरी तेज गति से फर्राटा भर कर तय की जा सकेगी। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण की अनुमानित अवधि से आठ महीने पहले बनकर तैयार हो गया है। इसे 28 माह में बना लिया गया है। उप्र सरकार का दावा है कि इसे अनुमानित लागत से करीब 12.72 प्रतिशत कम कीमत में बना लिया गया है। इससे सरकारी खजाने को 1132 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

विभिन्न एक्सप्रेस वे के जरिये दिल्ली से चित्रकूट तक की 630 किमी की दूरी को पूरा करने में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की हिस्सेदारी 296 किमी रहेगी। जबकि, डीएनडी फ्लाईवे नौ किमी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे 24 किमी, यमुना एक्सप्रेस वे 165 किमी और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे 135 किमी की हिस्सेदारी निभायेंगे।

एलओसी पार करके भारत में घुसी पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, इस्लामाबाद की रहने वाली है रोजिना

श्रीनगर (आरएनएस)। सेना ने बीती रात जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारत आई थी। अधिकारियों ने बताया कि महिला की पहचान पाकिस्तान में इस्लामाबाद के फिरोजबंदा इलाके की रोजिना (49) के रूप में हुई है।

अधिकारियों ने कहा कि रोजिना ने पुंछ के चक्र दा बाग में नियंत्रण रेखा को पार किया। उन्होंने कहा कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और सेना उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि पाकिस्तानी महिला किस मकसद से एलओसी पार करके भारत में घुसी थी।

कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ की जांच के आदेश

दूसरी ओर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में अधिकारियों ने आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच 19 जून को हुई मुठभेड़ की जांच के आदेश दिए हैं। उस मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गए थे। यह मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके के चंडीगाम इलाके में हुई थी।

लोलाब के एसडीएम को चंडीगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान की सीआरपीसी की धारा 176 के तहत पड़ताल करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि लोगों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी के पास इस विषय के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के भीतर अपना बयान दर्ज करा सकता है।

सूरीनाम में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हुए सम्मानित

बेंगलुरु (आरएनएस)। वैश्विक आध्यात्मिक गुरु एवं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को सूरीनाम में उनके द्वारा किए गए मानवतावादी कार्यों के लिए सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द यलो स्टार से सम्मानित किया।

चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपने संबोधन में कहा, हम आपके आभारी हैं कि वर्तमान और भविष्य में आने वाली पीढिय़ां आपके द्वारा दिए गए ज्ञान का अनुसरण करेंगी। आप शांति एवं सामंजस्य के मार्ग पर हम सभी का निर्देशन करें। सूरीनाम के लोग पूरे हृदय से आपका स्वागत करते हैं।

इस समारोह का आयोजन राष्ट्रपति निवास में किया गया। गुरुदेव ऐसे पहले एशियन हैं, जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी तक इतिहास में यह सम्मान राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को ही दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यह सम्मान एक आध्यात्मिक गुरु को दिया गया है। इस समारोह में सूरीनाम में भारत के राजदूत, माननीय डॉ शंकर बालचंद्रन भी मौजूद थे।

गुरुदेव ने अपने ट्वीट में कहा, मैं इस सम्मान का श्रेय आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षकों और स्वयं सेवकों को देना चाहता हूं, जिन्होंने देश में इतनी सराहनीय सेवा की है। मैं इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति जी और जजों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

गुरुदेव 21 वर्षों के बाद दक्षिण अमेरिका राष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, जहां सूरीनाम के रक्षामंत्री ने गुरुदेव का स्वागत किया। सुबह के समय, गुरुदेव देश के प्रमुख व्यापारी वर्ग से मिले और कार्य क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आध्यात्म की महत्ता पर बातचीत की। शाम के समय गुरुदेव ने पैरामारीबो में खचाखच भरे एंथोनी नेस्टी स्पोर्थल राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम में संबोधन किया। वहां गुरुदेव ने ध्यान कराया और वहां मौजूद हज़ारों लोगों से बातचीत की। आर्ट ऑफ लिविंग के दृष्टिकोण मेकिंग लाइफ ए सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए वहां मौजूद लोगों ने प्राचीन मंत्रोच्चारण की तरंगों और भजनों का आनंद उठाया।

राष्ट्रपति ने आई स्टैंड फॉर पीस की शपथ भी ली, जिसकी शुरुआत गुरुदेव ने एक वैश्विक अभियान के रूप में की ताकि शांतिपूर्ण प्रगति , एकता और सामंजस्य की ओर ध्यान खींचा जा सके।

जम्मू-कश्मीर : रूबिया ने कोर्ट में पहचाना, यासीन मलिक ने ही किया था अपहरण

नई दिल्ली (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने किया था। रूबिया ने शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत के सामने गवाही में यासीन मलिक समेत तीन आतंकियों की पहचान की, जिन्होंने उनका अपहरण किया था। रूबिया पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बहन हैं। यह पहली बार है, जब रूबिया को इस मामले में पेश होने के लिए कहा गया था। वे फिलहाल तमिलनाडु में रहती हैं। रूबिया का अपहरण 8 दिसंबर 1989 को हुआ था। उनकी रिहाई के लिए 13 दिसंबर को सरकार को 5 आतंकवादी छोडऩे पड़े थे। उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के गृहमंत्री थे। सीबीआई ने 1990 की शुरुआत में इस केस की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

रूबिया के वकील अनिल सेठी ने बताया कि वह सीबीआई?के सामने अपने पहले दिए गए बयान पर कायम हैं। उन्होंने जांच के दौरान उपलब्ध कराई गई तस्वीरों के आधार पर यासीन मलिक और तीन अन्य की पहचान की। अपहरण के 31 साल से अधिक समय बाद मलिक और नौ अन्य के खिलाफ अदालत ने पिछले साल जनवरी में आरोप तय किए थे। सेठी के मुताबिक सुनवाई की अगली तारीख 23 अगस्त तय की गई है। अगली तारीख पर रूबिया भी मौजूद रहेंगी। यासीन मलिक ने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खुद को व्यक्तिगत तौर पर जम्मू ले जाने की मांग की है। हालांकि यासीन को जम्मू लाया जाएगा या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं मिली है। रूबिया सईद के अपहरण को लेकर श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में 8 दिसंबर 1989 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

एफआईआर की कॉपी के मुताबिक, वे एक ट्रांजिट वैन में श्रीनगर के एक अस्पताल से अपने घर नौगाम के लिए जा रही थीं। वे पढ़ाई के बाद अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। वैन लाल चौक से होते हुए जब चानपूरा चौक के पास पहुंची। उसमें सवार 3 लोगों ने बंदूक के दम पर वैन को रोक लिया और रूबिया का अपहरण कर लिया। रिहाई के बदले जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने 5 आतंकियों हामिद शेख, अल्ताफ अहमद भट्ट, नूर मोहम्मद, जावेद अहमद जरगर व शेर खान को रिहा करने की शर्त रखी थी। शर्त पूरी होने के बाद ही रूबिया को छोड़ा गया। यासीन मलिक एक अलगाववादी नेता है और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा है। वह कश्मीर की राजनीति में हमेशा से ही सक्रिय रहा है। उस पर युवाओं को भडक़ाने और हाथों में बंदूक लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप है।

जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, नड्डा ने किया ऐलान

नई दिल्ली (आरएनएस)। भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। आज दोपहर में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी।

छह अगस्त को होगी वोटिंग

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 19 जुलाई तक होगा। इसके बाद 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 जुलाई तक नामांकन करने वाले उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होगी। इससे पहले दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा के दिल्ली हेडक्वॉर्टर पहुंचे।

न्यायिक रिक्तियों को न भरना लंबित मामलों का प्रमुख कारण : सीजेआई एन वी रमना

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमना ने न्यायपालिका में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के लिए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा न्यायिक रिक्तियों को न भरना मामलों के लंबित होने का प्रमुख कारण है। सीजेआई की प्रतिक्रिया जयपुर में अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के संबोधन के बाद आई।

सीजेआई एन वी रमना ने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक या दो चीजों पर प्रतिक्रिया दूं, जिसका उल्लेख कानून मंत्री ने किया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने पेंडेंसी के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा, जब हम न्यायाधीश भी देश से बाहर जाते हैं, तो हमें भी एक ही प्रश्न का सामना करना पड़ता है। एक मामला कितने साल चलेगा? आप सभी पेंडेंसी के कारणों को जानते हैं। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि प्रमुख महत्वपूर्ण कारण न्यायिक रिक्तियों को न भरना और न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं करना है।

सीजेआई ने अपने संबोधन में कहा, न्यायपालिका इन सभी मुद्दों को हल करने की कोशिश में हमेशा आगे है। मेरा एकमात्र अनुरोध है कि सरकार को रिक्तियों को भरने के साथ-साथ बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। नालसा सबसे अच्छा मॉडल है। यह एक सफलता की कहानी है। इसलिए उसी तर्ज पर, हमने पिछले मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में एक न्यायिक बुनियादी ढांचा प्राधिकरण का सुझाव दिया था। दुर्भाग्य से, इसे नहीं लिया गया था। हालांकि, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा।

सीजेआई ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का उदाहरण दिया जिसने पिछले साल लगभग 2 करोड़ मुकदमेबाजी और 1 करोड़ लंबित मामले निपटाए।

जेल में लगातार बढ़ रही कैदियों की आबादी पर चिंता व्यक्त करते हुए, सीजेआई ने कहा, भारत में हमारे पास 1378 जेलों में 6.1 लाख कैदी हैं। वे वास्तव में हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। जेल ब्लैक बॉक्स हैं। कैदी अक्सर अनदेखे, अनसुने नागरिक होते हैं।

उन्होंने कहा, जेलों का विभिन्न श्रेणियों के कैदियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों से संबंधित। ई-जेल पोर्टल के तहत नई पहल कैदी के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है। अब, एक कैदी के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी, जैसे कि उनकी कैद और लंबित अदालती मामलों का विवरण, बस एक क्लिक दूर है।

सीजेआई ने कहा, आज शुरू की गई एक और बड़ी पहल ई-मुलाकात की है। परिवार और समाज से लंबे समय तक अलगाव एक कैदी के मानसिक स्वास्थ्य और समाजीकरण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। इस पहल के माध्यम से, कैदियों के परिवार और शुभचिंतक निरंतर उनसे संपर्क में रह सकते हैं। ई-पैरोल एप्लिकेशन एक और बड़ी पहल है जिसके माध्यम से कैदियों के पास सामाजिक अस्तित्व और बातचीत की निरंतरता हो सकती है।

सीजेआई ने कहा, पुलिस का प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक कदम है। विवादों के लिए भी एडीआर की जरूरत होती है और इससे अदालतों पर बोझ कम होगा। उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों के साथ निष्कर्ष निकाला और कहा, लोकतंत्र की मेरी धारणा यह है कि इसके तहत सबसे कमजोर को वही अवसर मिलना चाहिए जो सबसे मजबूत है।